

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 भाद्रपद 19, 1946 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–13

संख्या 1122 / एक-13-2024-1-13099 / 2073—2020 लखनऊ, 10 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

#### प0आ0-302

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 601/1–13–2015–7क(18)–2014 दिनांक 31 अगस्त, 2015 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किये जाने हेतु लोपित हों, राज्यपाल अधिसूचित करती हैं कि जिला गौतमबुद्धनगर के सिवाय उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में समस्त परियोजनाओं के लिये समग्र रूप में सिंचित बहुफसली भूमि का अर्जन किसी भी मामले में उन जिलों के सिंचित बहु—फसली भूमि के कुल क्षेत्रफल की 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा।

राज्यपाल अग्रतर अधिसूचित करते हैं कि जिला गौतमबुद्धनगर में समस्त परियोजनाओं के लिए समग्र रूप में सिंचित बहु—फसली भूमि का अर्जन किसी भी मामले में जिला गौतमबुद्धनगर में सिंचित बहु—फसली भूमि के कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा।

> आज्ञा से, पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1122/1-13–2024-1-13099/2073-2020, dated September 10, 2024:

No. 1122/ 1-13-2024-1-13099/2073-2020

Dated Lucknow, September 10, 2024

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) and in supersession of notification no. 601/1-13-2015-7ka(18)-2014 dated August 31, 2015 Except as respects things done or ommitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to notify that the acquisition of irrigated multi croped land in aggregate for all projects in all districts of the State of Uttar Pradesh except district Gautam Budh Nagar shall in no case exceed 5 per cent of limits of the total area of irrigated multi-croped land of those districts.

The governor is further pleased to notify that the acquisition of the irrigated multi-croped land in aggregate for all projects in district Gautam Budh Nagar Shall in no case exceed 20 per cent of limits of the total area of irrigated multi-croped land in district Gautam Budh Nagar.

By order,
P. GURU PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ३४७ राजपत्र—२०२४—(८६२)—५९९ प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० २ सा० राजस्व—२०२४—(८६३)—1००० प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।